अपनी बात

दलाई लामा से बराक ओबामा की भेंट सराहनीय

तिब्बत समस्या के समाधान हेतु अमरीका द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं और इनसे तिब्बत समर्थक आंदोलन का मनोबल बढ़ा है। चीन द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तिब्बती धर्मगुरू परम पावन दलाई लामा से भेंट की। ओबामा ने तिब्बत समस्या के सामाधान से जुड़े मध्यम मार्ग अर्थात् वास्तविक स्वायत्तता संबंधी दलाई लामा के विचार को व्यावहारिक बताया। उन्होंने चीन सरकार को परामर्श दिया कि वह तिब्बत की निर्वासित सरकार तथा दलाई लामा के प्रतिनिधियों के साथ सार्थक वार्ता करे और तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता प्रदान करे। ज्ञातव्य है कि चीन के संविधान तथा क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्वायत्तता कानून में भी इस तरह के प्रावधान मौजूद हैं। इन्हें लागू नहीं करके चीन की सरकार अपने संविधान और कानून की स्वयं धज्जियाँ उड़ा रही है।

तिब्बत मामले में अमरीका की गंभीर चिंता का इससे भी पता चलता है कि वहाँ के वैदेशिक मामलों के विभाग ने तिब्बत के लिए एक विशेष समन्वयक नियुक्त किया है। यह समन्वयक अर्थात् पर्यवेक्षक तिब्बत में शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, धर्म–संस्कृति, वाणिज्य–व्यापार तथा मानवाधिकार की वस्तुस्थिति की जाँच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। गत दो–तीन वर्षों में ही सवा सौ से ज्यादा तिब्बती चीन द्वारा की जा रही क्रूरता के कारण आत्मदाह कर चुके हैं। शरीर के किसी अंग में मामूली चोट लगने पर भी पीड़ा होती है। इसलिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई शांतिप्रिय अहिंसक तिब्बती आंदोलनकारी अपनी खुशी प्रकट करने के लिए अपने ही शरीर को अपने ही हाथों आग लगा रहा है। सच्चाई है कि वह चीनी आतंक की ओर विश्व समुदाय का ध्यान आकर्शित करने के लिए ऐसा कर रहा है, ताकि साम्राज्यवादी चीन की दमनात्मक नीति पर तिब्बत में रोक लगे। वह परमपावन दलाई लामा को तिब्बत में ससम्मान वापस बुलाए जाने की मांग कर रहा है। ऐसी घटनाओं से अमरीका का विचलित होना स्वाभाविक है।

भारत सरकार को चाहिए कि वह भी तिब्बत के समर्थन में अमरीका के समान कदम उठाए। चीन के विरोध की चिंता किए बगैर भारत के राष्ट्रपति–प्रधानमंत्री दलाई लामा के साथ वार्ता करें। उन्हें सम्मानित करें। उनकी वास्तविक स्वायत्तता संबंधी प्रस्ताव को मानने के लिए चीन पर दबाव डालें। इसी प्रकार भारत सरकार का विदेश विभाग भी तिब्बत मामले में एक विशेष समन्वयक अर्थात् पर्यवेक्षक नियुक्त करे। उसे तिब्बत की बुरी हालत का अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपे और उसकी रिपोर्ट पर उपयुक्त कार्रवाई करे।

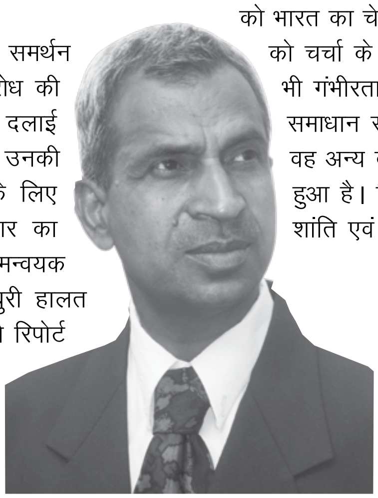

भारत में कई संगठन तिब्बत के पक्ष में सक्रिय हैं। ऑल पार्टी इंडियन पार्लियामेंटरी फोरम फॉर तिब्बत भी उनमें से एक है। इन सभी संगठनों को आपसी तालमेल बढ़ाकर अपने आंदोलन को जारी रखने की जरूरत है। संगठित प्रयास में ज्यादा शक्ति होती है। उपनिवेशवादी चीन की तिब्बत के मामले में हठधर्मिता बरकरार है। इसी 3 जुलाई 2014 को मैकमोहन समझौते के सौ साल हो रहे हैं। इस समझौता वार्ता में चीन तथा ब्रिटिश भारत के साथ स्वतंत्र देश तिब्बत भी शामिल हुआ था। शिमला में संपन्न इस समझौते पर चीन ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। वह तिब्बत को हड़पना चाहता था। यह भी चीन का हठ था। इस तरह स्पष्ट है कि उपनिवेशवादी चीन की नीति तिब्बत को बर्बाद करने की नीति है। वह ऐतिहासिक प्रमाणों को विकृत करके भ्रामक प्रचार कर रहा है कि तिब्बत पर उसका कब्जा जायज है।

भारत चूँकि तिब्बत का पडो़सी है, इसलिए तिब्बत पर चीन के अवैध नियंत्रण से भारत बुरी तरह प्रभावित है। तिब्बत का इस्तेमाल चीन की सरकार भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कर रही है। तिब्बत के साथ–साथ भारत की भी सामाजिक–राजनीतिक–सांस्कृतिक–धार्मिक–आर्थिक–सामरिक व्यवस्था खतरे में पड़ गई है। जब तक भारत और चीन के बीच तिब्बत एक स्वतंत्र मध्यस्थ राज्य (बफर स्टेट) था तब तक चीन सरकार भारत की सीमा से काफी दूर थी। तिब्बत पर अवैध नियत्रंण करके ही चीन हमारी भारतीय सीमा से जुड़ा था। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार परंपरागत रूप से भारत एवं तिब्बत की सीमा जुड़ी होती थी। उन दिनों भारत–चीन संबंध भी प्रगाढ़ थे।

सोलहवीं लोकसभा के आम चुनाव इसी वर्ष हैं। इस अवसर पर तिब्बत का मुद्‍दा राजनेताओं को जोरदार तरीके से उठाना चाहिए। तिब्बत का सवाल भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा का सवाल है। यह मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक मुल्यों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा मानवीय आदर्शों की सुरक्षा का सवाल है। तिब्बतियों का साथ देकर हम अपनी राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दलाई लामा जी बौद्ध धर्मगुरू हैं। भगवान बुद्ध का दर्शन भारत से ही अन्य देशों में पहुँचा। इसीलिए दलाई लामा जी भारत को अपना गुरू मानते हैं तथा तिब्बत को भारत का चेला। चुनावी वर्ष में भारतीय अपने चेले तिब्बत के संकट को चर्चा के केन्द्र में लायें। इस कार्य में भारतीय मीडिया को और भी गंभीरता के साथ जिम्मेदारी निभानी होगी। तिब्बत समस्या के समाधान से भारत के साथ–साथ चीन का भी भला होगा। अभी वह अन्य देशों की नज़र में घोर उपनिवेषवादी तथा क्रूर देश बना हुआ है। तिब्बत समस्या का समाधान एशिया समेत पूरे विश्व में शांति एवं मैत्री की राह को प्रशस्त करेगा।

प्रो0 श्यामनाथ मिश्रा

पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

खेतड़ी (राज.)

ek-&9829806065] 8764060406

E-mail & Facebook :- shyamnathji@gmail.com

स्पेन के निचले सदन ने तिब्बत में नरसंहार के बारे में कानून में किया संशोधन

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 13 फरवरी, 2014)

स्पेन की संसद के निचले सदन ने 11 फरवरी को एक संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है जिसके द्वारा दूसरे देशों हुए अत्याचारों के बारे में मुकदमा चलाने के न्यायपालिका के अधिकारों को सीमित किया गया है। इस बिल को सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पापुलर पार्टी द्वारा आगे बढ़ाया गया था। इस संशोधन प्रस्ताव को 163 के मुकाबले 179 मतों से पारित कर दिया गया और विपक्षी दलों से किसी ने भी समर्थन नहीं किया। इसका तात्कालिक उद्देश्य चीन के पांच वरिष्ठ रिटायर नेताओं के खिलाफ अधिकृत तिब्बत में नरसंहार में लिप्तता के लिए चलाए जा रहे मुकदमे को खत्म करना है।

प्रस्तावित संशोधन कानून की मानवाधिकार संगठनों और स्पेन के विपक्षी दलों ने आलोचना की है। डब्ल्यूएसजेड की 11 फरवरी की रिपोर्ट के अनुसार इस बिल से अब स्पेन की अदालतों में चल रहे दूसरे मानवाधिकार मामलों को भी खत्म किया जा सकता है। यह बिल पारित हो जाने के बाद अब कानून बन जाने की पूरी संभावना है क्योंकि वहां के ऊपरी सदन सीनेट में भी सत्तारूढ़ पॉपुलर पार्टी का बहुमत है। प्रस्तावित संशोधन को उचित ठहराते हुए कांग्रेस में पॉपुलर पार्टी प्रतिनिधिमंडल के प्रवक्ता अलफॉन्सो अलोन्सो ने जनवरी, 2014 में कहा था कि सार्वभौमिक न्याय के तहत काफी कुछ करने की बात है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हो पाया और इससे राजनयिक टकरावों से ज्यादा और कुछ हासिल नहीं हो रहा।

स्पेन की सरकार ने दूसरी बार अदालत के सार्वभौमिक न्यायिक अधिकार को सीमित करने का प्रयास किया है। इसके पहले वर्ष 2009 में एक राजनयिक दबाव के बाद, खासकर चीन के दबाव को देखते हुए, प्रधानमंत्री जोस लुइस रोड्रिग जपाटेरो की समाजवादी सरकार ने सार्वभौमिक न्यायिक क्षेत्र के तहत अभियोग के लिए तीन अलग–अलग जरूरतों की शर्त रखकर न्यायिक अधिकारों को सीमित किया था। इसकी वजह से अब इस तरह के अत्याचारों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को स्पेन के क्षेत्र में रहने वाला होना चाहिए, पीड़ित का स्पेन का नागरिक होना चाहिए और स्पेन से कोई प्रासंगिक जुड़ाव जरूर होना चाहिए।

मौजूदा संशोधन से तो इस तरह के अधिकार और सीमित होंगे। अब नरसंहार के कथित मामलों में केवल स्पेन के नागरिक या स्पेन में रहने वाले विदेशी नागरिकों पर ही अभियोग चलाया जा सकता है। इसके अलावा यह कहा गया है कि वादी को न केवल स्पेन का नागरिक होना चाहिए बल्कि कथित यातना होने के दौरान भी उन्हें स्पेन का नागरिक रहना चाहिए। इस प्रकार ये सभी बदलाव वास्तव में तिब्बत नरसंहार मामलों को खत्म करने के लिए लाए गए हैं, जो वर्ष 2006 से चीन के पूर्व राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव जियांग जेमिन, पूर्व प्रधानमंत्री ली पेंग और तीन अन्य शीर्ष चीनी नेताओं के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। स्पेन के एक स्वयंसेवी संगठन तिब्बत सपोर्ट कमेटी, जो कि इन मामलों में मुख्य वादी रहा है, इसके अध्यक्ष एलन कैंटोस ने कहा, "यह कानून खासकर चीन के इशारे और आग्रह पर तैयार किया गया है। यह पूरी तरह से अनैतिक है।" अब सवाल यह है कि क्या यह सुधार तिब्बत में नरसंहार के लिए चल रहे मामलों में पिछली तिथि से लागू होगा?

एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वाच जैसे कई मानवाधिकार संगठनों ने एक खुल पत्र पर हस्ताक्षर कर प्रस्तावित कानून को "सार्वभौमिक न्यायिक क्षेत्र के लिए विनाशकारी बताया है और स्पेन की इस अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता के प्रति भी किसी भी गंभीर अपराध के दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।"

वर्ष 2013 में तिब्बत में हुआ मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 2 मार्च)

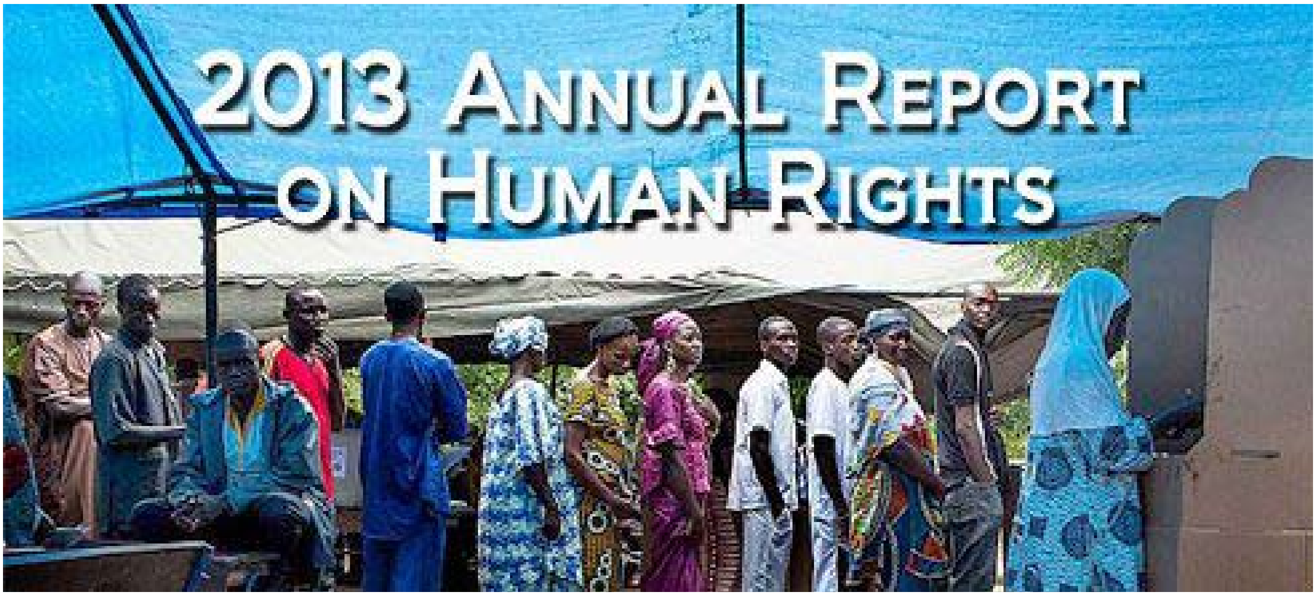

अमेरिका के विदेश विभाग ने 27 फरवरी को कहा कि वर्ष 2013 में तिब्बत में चीनियों द्वारा खूब दमन किया गया। अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2013 की सालाना मानवाधिकार कंट्री रिपोर्ट में एक विशेष तिब्बत खंड के अंतर्गत यह जानकारी दी है। इस रिपोर्ट के आने के छह दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबाामा ने तिब्बत के निर्वासित आध्यात्मिक नेता दलाई लामा का व्हाइट हाउस में स्वागत किया था।

इस रिपोर्ट में तिब्बत में गंभीर मानवाधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनमें अनिश्चित काल के लिए तिब्बतियों की मनमाने तरीके से गिरफ्तारी, बिना मुकदमा चलाए उनको मौत के घाट उतार देना, प्रताड़ना, मनमाने तरीके से हिरासत में लेना, बिना मुकदमे के कैद में रखना और नजरबंदी शामिल है। इसमें खासकर हाल में चीन में लागू नीतियों की जानकारी दी गई है जिसके मुताबिक "आत्मदाह करने वाले लोगों के दोस्तों, रिश्तेदारों और सहयोगियों को दंडित किया जाता है।" इसमें यह कहा गया है कि नई नीति की वजह से 90 तिब्बतियों को सजा सुनाई गई है (क्विंघई और गांसू प्रांत में) और इनमें एक को सजा–ए–मौत भी शामिल है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि तथाकथित तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में वास्तविक स्वायत्तता नाम की कोई चीज नहीं है और अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत तथा अनूठे प्राकृतिक पर्यावरण को बचाने में तिब्बतियों की कोई सार्थक भूमिका नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है, "आर्थिक एवं सामाजिक रूप से हाशिये पर रहना" तिब्बतियों में असंतोष की प्रमुख वजह है।

रिपोर्ट में यह भी विस्तार से बताया गया है कि चीन किस तरह से तिब्बत के असल हालात को छुपा रहा है। खासकर विदेशी राजनयिकों, पत्रकारों को लगातार तिब्बती इलाके में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। यहां तक कि 10 मार्च की तिब्बती जनक्रांति दिवस जैसे राजनीतिक रूप संवेदनशील वर्षगांठों आदि के मौके पर विदेशी पर्यटकों को भी तिब्बत जाने की इजाजत नहीं दी जा रही।

अमेरिकी विदेश विभाग के सालाना वैश्विक देशवार रिपोर्ट में वर्ष 2002 से कांग्रेस ने अनिवार्य रूप से तिब्बत पर एक खंड रखना अनिवार्य कर दिया है। चीन ने इसके बदले में अमेरिका में खराब मानवाधिकार हालात की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि "मानवाधिकारों पर दुनिया का जज" बनने वाली अमेरिकी सरकार "ने हाल में जारी मानवाधिकार रिपोर्ट में दुनिया के करीब 200 देशों के मानवाधिकारों के बारे में मनमाने हमले और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां की हैं। अमेरिका में वर्ष 2013 के मानवाधिकारों के बारे में यह रिपोर्ट चीन के स्टेट कौंसिल यानि कैबिनेट के सूचना कार्यालय ने जारी की है।

परमपावन ने ओबामा से मुलाकात, तिब्बत और चीन के बारे में दिया संबोधन

(28 फरवरी, 2017, दलाई लामा डॉट कॉम)

वाशिंगटन डीसी में 6 मार्च, 2014 को कैपिटल हिल में हाउस की अल्पसंख्यक नेता नैंसी पेलोसी के साथ परमपावन दलाई लामा और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के निर्वाचित नेता सिक्योंग डॉ. लोबसांग सांगे। फोटोः सोनम जोकसांग

लॉस एंजिलिस का आसमान असामान्य रूप से धुंधला है क्योंकि आज या कल बारिश का अनुमान है, ऐसे मौसम वाले सुबह परमपावन दलाई लामा हफिंगटन पोस्ट के स्टुडियो की तरफ बढ़ते हैं. सीनियर एडिटर विलो बे ने एक इंटरव्यू में उनसे बात की जिसका हफिंगटन पोस्ट के सभी नौ अंतरराष्ट्रीय संस्करणों में लाइव स्ट्रीमिंग किया गया।

सबसे पहले उन्होंने परमपावन से पिछले हफ्ते राष्ट्रपति ओबा. मा से हुई मुलाकत के बारे में पूछा। दलाई लामा ने उनसे बताया कि एक पुराने दोस्त होने के नाते वह अपनी तीन प्रतिबद्धताओं के प्रति अद्यतन थेः मानवीय मूल्यों, धार्मिक सौहार्द को बढ़ावा देना और तिब्बती संस्कृति का संरक्षण। जब उन्होंने परमपावन से यह सवाल किया कि क्या पूंजीवाद के प्रति उनका रवैया वास्तव में इतना बदल गया है, जैसा कि पिछले हफ्ते की मुलाकात के बाद खबरों में आया था। इस पर उन्होंने कहा, "यह प्रेरणा पर निर्भर करता है। लोग यदि पैसा बनाते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने भोग–विलास की चीजों को जुटाने के लिए करते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। इसका कुछ इस्तेमाल दूसरों के फायदे के लिए करना ही सही तरीका है।"

एकेडमी अवॉड्र्स की चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में उन्होंने एक भी मूवी नहीं देखी है। उन्होंने कहा कि वह रेडियो पर बीबीसी सुनते हैं जो उनके लिए सूचना का मुख्य स्रोत होता है। इस सवाल पर कि हम दुनिया में और खुशी लाने के लिए क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि हमें काफी समझदारी से गर्मजोशी को बढ़ावा देना चाहिए।

लंच के बाद परमावन का स्वागत कैलिफोर्निया साइंस सेंटर में वहां के निदेशक जेफ रुडोल्फ और श्रीमती ऑस्चिन ने स्वागत किया। सबसे पहले उन्होंने टीवी एवं रेडियो के वरिष्ठ पत्रकार और अपने पुराने दोस्त लैरी किंग को इंटरव्यू दिया। उन्होंने बताया कि उन्होने राष्ट्रपति ओबामा से अपनी तीन प्रतिबद्धताओं के बारे में बात की है जिन्होंने तिब्बत के हालात के बारे में उनसे पूछा था। किंग ने पूछा था कि क्या मानवाधिकारों के मामले में चीन पर दबाव बनाने के मामले में अमेरिका पर्याप्त दबाव बना रहा है तो परमपावन ने कहा, "पूरी दुनिया में ज्यादा लोकतंत्र, खुलेपन और स्वाधीनता की हवा है। चीन दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, लेकिन उसका भविष्य बाकी दुनिया पर निर्भर करता है, इसलिए उसे भी दुनिया की हवा के साथ चलना चाहिए।" क्या वह अपनी मातृभूमि में वापस लौटने की वास्तव में संभावनता देखते हैं, इस सवाल पर उन्होंने कहाः "जी हां, चीन बदल रहा है जैसा कि हमने माओ, देंग जियोपिंग, जियांग जेमिन और हू जिनताओ के चार युगों में देखा है।"

जब लैरी किंग ने उनके सामान्य दिन के बारे में पूछा तो परमपावन ने जवाब दिया, वह भी एक इंसान हैं, वह भी सोते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन एक बौद्ध भिक्षु होने के नाते वह अपने उन 253 प्रतिज्ञाओं से भी बंधे हुए हैं जो इस बारे में है कि किस तरह से खाना, सोना, चलना और बात करना है। उन्होंने बताया कि वह सुबह 3 बजे उठ जाते हैं और इसके बाद प्रार्थना और ध्यान करते हैं। उन्होंने कहा कि दो तरह के ध्यान होते हैं, एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना और विश्लेषणात्मक ध्यान करना, इसमें से वह अपने दिमाग और भावनाओं के विश्लेषण पर ज्यादा समय लगाते हैं।

अंत में उनसे जब यह सवाल किया गया कि वह दुनिया में किस तरह से याद किया जाना चाहेंगे। इस पर परमपावन ने कहा कि एक बौद्ध भिक्षु होने के नाते उन्हें नाम और प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है। उन्होंने न्यूयॉर्क का एक वाकया याद करते हुए बताया जब एक पत्रकार ने उनसे उनकी विरासत के बारे में पूछा और तब उन्होंने कहा था कि उनके लिए इसके बारे में सोचना उपयुक्त नहीं है। कुछ समय बाद उस पत्रकार ने फिर उनसे वही सवाल पूछा और उन्होंने फिर यही जवाब दिया। जब उस पत्रकार ने तीसरी बार यही सवाल किया तो वह अपना आपा खो बैठे। परपमावन ने बताया कि जब वह और पत्रकार एक साल बाद फिर मिले तो दोनों खूब हंसे।

इसके बाद लैरी किंग परमपावन को सैमुअल ऑस्चिन पैविलियन लेकर गए जो स्पेस शटल एंडेवर का ठिकाना है। वहां

21वीं सदी में नेतृत्व के सवाल पर विचार सुनने के लिए लॉस एंजिलिस के सैकड़ों प्रख्यात लीडर्स उनका इंतजार कर रहे थे। इरिक बेनेट के गीत 'What the World needs now is Love' के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद पत्रकार एन्नी करी मंच पर मॉडरेटर के रूप में आईं। उन्होंने कहा कि उनके पास दर्शकों की तरफ से परमपावन से पूछने के लिए तमाम सवाल हैं। सबसे पहला सवाल यह था कि यदि किसी व्यक्ति की संगठित धर्म में रुचि न हो तो वह आंतरिक शांति का अनुभव कैसे कर सकता है। अपने जवाब में परमपावन ने कहा कि वह धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देते हैं लोगों को यह बताने के लिए दुनिया के सभी धर्मों मे एक ही तरह के बुनियादी मानवीय मूल्य होते हैं जिन्हें वह धर्मनिरपेक्ष मूल्य कहते हैं। उन्होंने कहा कि गुस्से जैसी विनाशक भावनाएं हमारी आंतरिक शांति को नष्ट करते हैं जो कि अवहेलना से जुड़ा होता है, जबकि रचनात्मक भावनाएं कारण से जुड़ी होती हैं, हम पहले को घटा सकते हैं और दूसरे को बढ़ा सकते हैं।

जब स्वयं यानि आत्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "यह एकल, ठोस और आत्मनिर्भर जैसा लगता है जैसा कि हमारे ऊपर यह अंतरिक्ष यान है। हालांकि, जिस तरह से अंतरिक्ष यान बहुत सारे छोटे–छोटे टुकड़ों से बना है उसी तरह आत्म के भी बहुत से पहलू होते हैं।"

एक असामान्य सवाल पूछा गया, "क्या आप अपने साथ कोई ब्रीफ केस रखते है, और यदि हां तो उसमें क्या होता है? जवाब भी अप्रत्याशित था। परमपावन ने कत्थई रंग के सूती कपड़े से बने अपने कंधे पर लटकने वाले झोले को दिखाते हुए यही वह अपने साथ लेकर चलते हैं। अब बात यह थी कि उसके अंदर क्या है। उन्होंने बैग में से दो चॉकलेट निकाले जो लॉस एंजिलिस की फ्लाइट में उनको मिला था। उन्होंने एक चॉकलेट एन्न करी और दूसरा शारोन स्टोन को दिया। इसके बाद उन्होंने बैग में से अपना टूथब्रश, पेस्ट, अतिरिक्त चश्मा दिखाया और यह भी दिखाया कि वह साथ में बुद्ध की मूर्ति भी रखते हैं। शरोन स्टोन ने कहा कि क्या वह मूर्ति देख सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि यह कुछ चीजों से लपेटा गया है। उन्होंने बताया कि जब उनकी दीक्षा हुई थी तब उन्हें एक बौद्ध भिक्षु ने एक बौद्ध मूर्ति दी थी और जब उन्होंने तिब्बत छोड़ा तो उनके पास एक बड़ी, भारी मूर्ति थी जिसे साथ में ढोना सुविधाजनक नहीं था। उनके पास जो मौजूदा मूर्ति है वह एक भारतीय पंडित स्मृतिजनककीर्ति द्वारा चिकनी मिट्टी से बनाया गया था जो कई शताब्दी पहले तिब्बत गए थे। जब उनके अनुवादक की मौत हो गई तो उनके पास लोगों को यह बताने का कोई तरीका नहीं था कि वह कौन हैं और उन्होंने एक चरवाहे की तरह जिंदगी गुजारी। अपने जानवरों की रखवाली के दौरान वह बैठे–बैठे बुद्ध की मूर्तियां और चित्र बनाते रहते और उनमें से ही एक मूर्ति परमपावन के पास है।

कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर ग्रे डेविस ने परमावन दलाई लामा को वहां आने के लिए धन्यवाद दिया और उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया जो वहां आए थे।

अमेरिका ने तिब्बत के लिए नया विशेष समन्वयक नियुक्त किया

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 22 फरवरी, 2014)

अमेरिका ने डॉ. सारा सेवाल को तिब्बत मसले का नया विशेष समन्वयक नियुक्त किया है।

राष्ट्रपति बराक ओबामा के 21 फरवरी को व्हाइट हाउस में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से मुलाकात की पूर्व संध्या पर अमेरिका ने डॉ. सारा सीवाल को तिब्बतन मसलों के लिए नया विशेष समन्वयक नियुक्त किया है। वह अमेरिका की नागरिक सुरक्षा, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की उप मंत्री हैं।

डॉ. सीवाल एक प्रख्यात अकादमिक हस्ती हैं और इसके पहले भी सरकार में उन्होंने तमाम तरह के अनुभव हासिल किये हैं। वह राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल में शांति निर्माण एवं मानवीय सहायता के लिए उप सहायक विदेश मंत्री थीं। वह राष्ट्रपति ओबामा के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति बदलाव टीम की भी हिस्सा थीं। हार्वर्ड एवं ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन करने वाली रोड स्कॉलर डॉ. सीवाल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जॉन एफ कैनेडी स्कूल में पब्लिक पॉलिसी की सीनियर लेक्चरर रह चुकी हैं और वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कार सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स पॉलिसी की प्रमुख थीं।

तिब्बत मसले के लिए विशेष समन्वयक का पद वर्ष 2002 के तिब्बत नीति अधिनियम के तहत सृजित किया गया था। इस पद के तहत डॉ. सीवाल की जिम्मेदारी दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों के साथ चीन सरकार के बीच वार्ता को बढ़ावा देने और तिब्बत के बारे में अमेरिकी सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के बारे में समन्वय कायम करना है।

डॉ. सीवाल तिब्बत मसलों के लिए अमेरिका की पांचवीं विशेष समन्वयक है। उनके पहले इस पद पर मारिया ओटेरो, पाउला दोब्रियांस्की, स्वर्गीय जूलिया ताफ्त और ग्रगोरी क्रेग रह चुके हैं।

दलाई लामा से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ओबामा ने तिब्बत पर गहरी चिंता जताई

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 23 फरवरी, 2014)

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस के मैप रूम में दलाई लामा से मुलाकात की। व्हाइट हाउस फोटोः पीट सूजा, 21 फरवरी, 2014

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गत 21 फरवरी को व्हाइट हाउस में तिब्बत के निर्वासित आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से मुलाकात के दौरान तिब्बत में बिगड़ती मानवाधिकार की स्थिति पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने तिब्बत की विशिष्ट धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई परंपरा के संरक्षण लिए अपना समर्थन देने की बात दोहराई।

सुबह की यह मुलाकात करीब एक घंटे चली और इस दौरान राष्ट्रपति ओबामा ने चीन सरकार के साथ मिलकर तिब्बत के मसले को हल करने के लिए दलाई लामा के मध्यम मार्ग नीति को भी समर्थन दिया। उन्होंने चीन से यह आह्वान किया कि वह बिना किसी पूर्व शर्त के परमपावन के प्रतिनिधियों के साथ रचनात्मक वार्ता करे। दोनों के बीच यह मुलाकात चीन द्वारा तमाम तरह की चेतावनी, धमकियों, कड़वी आलोचनाओं और निंदाओं के बावजूद हुई।

धर्मशाला, भारत स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रमुख सिक्योंग लोबसांग सांगे ने कहा, "यह मुलाकात अमेरिकी सरकार और वहां की जनता के लोकतंत्र और स्वाधीनता के प्रति लगातार प्रतिबद्धता को दर्शाता है।" इसी तरह एएफपी की 22 फरवरी की खबर के अनुसार उन्होंने कहा, "इससे तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बतियों को एक बहुत ही ताकतवर संदेश मिला है क्योंकि इससे उनके अंदर एक तरह की उम्मीद पैदा हुई है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है और दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति उनकी आवाज सुन रहा है।" उनका कहना है कि, "परमपावन दलाई लामा के प्रति जो सम्मान दिखाया गया है, उसका दुनिया भर के और खासकर तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बतियों के लिए खासा महत्व है।"

वाशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल पर 6 मार्च, 2014 को आयोजित एक बैठक के दौरान सिक्योंग डॉ. लोबसांग सांगे, हाउस की अल्पसंख्यक नेता नैंसी पेलोसी (डी–सीए), परमपावन दलाई लामा, व्हाइट हाउस के स्पीकर जॉन बोहनर (आरा–ओएच) और हाउस के बहुसंख्यक नेता एरिक कैंटोर (आर–वीए)। फोटोः सोनम जोकसांग

इस बारे में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति ने इस अमेरिकी पक्ष को दोहराया है कि तिब्बत चीन जनवादी गणतंत्र का हिस्सा है और अमेरिका तिब्बत की आज़ादी का समर्थन नहीं करता। प्रवक्ता ने कहा कि दलाई लामा ने भी कहा है कि वह तिब्बत को आज़ाद करने की मांग नहीं कर रहे और उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके प्रतिनिधियों तथा चीन सरकार के बीच बातचीत फिर शुरू होगी। इसके पहले 20 फरवरी की तय मुलाकात की घोषणा करते हुए ओबामा प्रशासन ने चीन की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा था कि वह 1989 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता से "अंतरराष्ट्रीय रूप से सम्मानित एक धार्मिक और सांस्कृतिक नेता की हैसियत से मिल रहे हैं।"

साथ ही, चीन के प्रति राजनीतिक संवेदनशीलता को प्रकट करते हुए यह मुलाकात राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास में ग्राउंड फ्लोर पर स्थित मैप रूम में आयोजित की गई, न कि वेस्ट विंग में स्थित ओवल ऑफिस में नहीं, जहां आमतौर पर ओबामा विदेशी नेताओं और अन्य हस्तियों से मिलते हैं।

इसके अलावा, दलाई लामा का प्रवेश इतना व्यवस्थित था कि उन्हें व्हाइट हाउस के प्रेस कर्मचारी भी नहीं देख पाए और फोटोग्राफर्स को इस मुलाकात की तस्वीरें भी नहीं लेनी दी गई। बाद में व्हाइट हाउस द्वारा खुद ही मुलाकात की फोटो जारी की गई।

इस मुलाकात की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता कैतिलीन हेडेन ने कहा था, "अमेरिका दलाई लामा के मध्यम मार्ग नीति का समर्थन करता है जिसमें यह कहा गया है कि तिब्बत के अलग होने या आज़ादी की मांग नहीं की जाएगी बल्कि तिब्बत को चीन का ही एक हिस्सा माना गया है।"

हेडेन ने कहाः "हम चीन के तिब्बती इलाकों में लगातार बढ़ रहे तनाव और मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति को लेकर चिंतित हैं। हम चीन सरकार से यह अनुरोध करते रहेंगे कि वह तनाव को कम करने के लिहाज से बिना किसी पूर्व शर्त के दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों के साथ वार्ता फिर से शुरू करे।"

दलाई लामा ने सार्वजनिक तौर पर तिब्बत की आज़ादी की मांग के लिए अभियान चलाना बंद कर दिया है और उन्होंने तिब्बत के राष्ट्र और सरकार प्रमुख के रूप में 369 साल पुरानी ऐतिहासिक भूमिका को भी छोड़ दिया है, लेकिन चीन लगातार उनको अलगाववादी बताते हुए उनकी आलोचना करता है और उनसे या उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी से बात करने से इनकार करता रहा है।

यह दलाई लामा की श्री ओबामा के साथ चौथी मुलाकात है और इसमें से तीन मुलाकात उन्होंने उनके राष्ट्रपति रहने के दौरान किये हैं। इनमें 18 फरवरी, 2010 और 16 जुलाई, 2011 को व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात शामिल है जिस पर अपेक्षित रूप से चीन सरकार ने काफी नाराजगी जताई थी। ओबामा के साथ दलाई लामा की पहली मुलाकात वर्ष 2005 में सीनेट की विदेश संबंध कमिटी में तब हुई थी, जब ओबामा अमेरिका के सीनेटर थे।

वर्ष 2009 में ओबामा ने चीन के तय दौरे से पहले दलाई लामा से मिलने से इनकार किया था, तब उनके इस निर्णय की काफी आलोचना की गई थी। वर्ष 2010 में उन्होंने चीन से लौटने के बाद दलाई लामा से मुलाकात की। इस बार श्री ओबामा के अप्रैल में एशिया के दौरे से पहले यह मुलाकात हुई है, हालांकि, ओबामा की चीन जाने की योजना नहीं है।

प्रतिगामी कदम

तिब्बत में ज्यादती के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराने से रोकने की स्पेन सरकार की कोशिश क्या वैश्विक पुलिसिंग का खत्म होना है?

डेविड बॉस्को, 15 फरवरी, फॉरेन पॉलिसी

चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन और पूर्व प्रधानमंत्री ली पेंगे। फाइल फोटो

चीन अंतरराष्ट्रीय कानूनों से निपट रहा है और ऐसा लगता है कि उसे इसमें एक बड़ी जीत मिलने वाली है। केंद्रबिंद पूर्वी चीन के विवादित जल क्षेत्र नहीं बल्कि तिब्बत है–और सबसे नवीनतम कानूनी ड्रामा स्पेन की अदालतों और संसद में चल रहा है। करीब दो दशकों से ऑडिएंसियां नेशनल (राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहुंच रखने वाली विशेष न्यायिक ईकाई) सुदूर होने वाली ज्यादती के आरोपों की जांच के लिए "सार्वभौमिक न्यायिक क्षेत्र) का इस्तेमाल करती रही है जैसे रवांडा, इजरायल और अमेरिका के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर लगे आरोपों पर। कुछ मामलों का स्पेन या स्पेन के नागरिकों का बहुत कम ही संबंध रहा है। लेकिन यह मायने नहीं रखता था, जजों ने इस बात पर जोर दिया था कि स्पेन का कानून और सार्वभौमिक न्यायिक क्षेत्र की व्यापक अवधारणा से यह साफ होता है कि कोई भी राष्ट्रीय कानूनी प्रणाली दुनिया में किसी भी जगह हुए गंभीर अपराध के लिए मुकदमा चला सकती है। इन मुकदमों में चिली के पूर्व तानाशाह अगस्तो पिनोश के खिलाफ 1998 में शुरू हुआ प्रसिद्ध मामला भी था जो देश की न्यायिक सक्रियता से राजनयिक कीमत चुकाने से परेशान थे। सत्तारूढ़ दल पार्टिडो पॉपुलर के एक प्रवक्ता ने कहा था कि इन मामलों से केवल 'राजनीतिक' टकराव ही पैदा होंगे और पूर्व राष्ट्रपति जोस मारिया अजनार ने इसकी आलोचन करते हुए कहा था कि स्पेन "सार्वभौमिक पुलिस" बनना चाहता है। स्पेन की न्यायपालिका में भी कई मुकदमे विवादास्पद रहे हैं। वर्ष 2012 की शुरुआत में स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने पिनोशे की जांच मामले की अगुवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के जज बालतासार गार्जन को निलंबित कर दिया। कोर्ट ने की जांच में यह नतीजा निकाला गया कि गार्जन ने बाद के एक मुकदमे में अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया था, इससे प्रभावी तरीके से उनका करियर खत्म हो गया। कई प्रेक्षकों ने इस कार्रवाई को

इस बात का प्रमाण माना कि किस तरह से कई वरिष्ठ जज गार्जन से खफा थे, जिस तरीके से वे अंतरराष्ट्रीय स्तर की जांच कर सुर्खियां बटोर रहे थे।

लेकिन कानूनी प्रावधान बरकरार रहने से गार्जन को किनारे किये जाने के बाद भी सार्वभौमिक न्यायिक क्षेत्र वाले मामले सामने आते रहे। 10 फरवरी, सोमवार को स्पेन की एक अदालत ने पूर्व चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन, पूर्व प्रधानमंत्री ली पेंग और कई वरिष्ठ चीनी अधिकारियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया। तिब्बत में दमन और उत्पीड़न को आधिकारिक बना देने के लिए ये लोग मुख्य आरोपी हैं। जज ने कहा कि दोनों नेता उन अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण रखते थे जिन्होंने अशांत इलाके में प्रताड़ना और अन्य अपराध करने के आदेश दिए थे। स्पैनिश कोर्ट के इस आदेश से चीन काफी नाराज हुआ और उसने इससे दोनों देशों के रिश्तों की सेहत पर आंच को लेकर सार्वजनिक चिंता जाहिर करने में हिचक नहीं दिखाई। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "इस मामले में सही तरीके से निपटा जाता है या नहीं यह रिश्तों के स्वस्थ विकास से जुड़ा है। हमें उम्मीद है कि स्पेन की सरकार सही और गलत का फर्क समझ सकेगी।"

चीन जो कुछ भी कहना चाह रहा है उसे मैड्रिड निश्चित रूप से समझता होगा। डूबती अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए उन्हें चीन के साथ व्यापार बढ़ाने को प्राथमिकता देनी होगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसी सोच के साथ कंजर्वेटिव पार्टिडो पॉपुलर ऐसा विधेयक लेकर आया है जिसके मुताबिक किसी ऐसे मामले की ही जांच की जा सकेगी जिसमें स्पेन से कुछ जुड़ाव हो।

इस विधेयक के प्रारूप में कहा गया है कि ऐसे जांच में शामिल संदिग्ध व्यक्ति या तो स्पेन का नागरिक हो या कम से कम स्पेन की भूमि पर रहता हो। मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि इस कानून से "जघन्यतम अपराधों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की स्पेन की प्रतिबद्धता जड़ से उखड़ जाएगी।"

तिब्बत मामले में शामिल आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया है कि स्पेन के सांसद चीनी दबाव में आ गए हैं। तिब्बत में जन्मे आंदोलनकारी थुबटेन वांगछेन ने स्पेन के अखबार अल पाइस से कहा, "अभी तक स्पेन की इस बात के लिए प्रतिष्ठा रही है कि वहां अमेरिका और जर्मनी जैसे अच्छे जज हैं। लेकिन अब मानवाधिकारों की रक्षा के मामले में स्पेन की प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है और यह सब धन की वजह से हो रहा है। लंदन यूनिवर्सिटी में कानून के प्रोफेसर केविन जॉन हेलर भी आर्थिक प्रभाव की वजह से न्याय पर आ रही आंच से चिंतित हैं। उन्होंने कहा, "कानून में बदलाव के पीछे पूरी तरह से ऐसी प्रेरणा लग रही है कि स्पेन असल में चीन को अलग–थलग होने से बचाना चाहता है, जिसके साथ उसके आर्थिक रिश्ते लगातार महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।

स्पेन ऐसा पहला देश नहीं है जिसने ताकतवर देश के दबाव में सार्वभौमिक न्यायिक क्षेत्र पर पुनर्विचार किया हो। वर्ष 2003 में अमेरिकी अधिकारियों ने बेल्जियम प्रशासन पर भी ऐसा ही दबाव बनाया था, जब वहां की एक अदालत ने इराक युद्ध के दौरान संभावित अमेरिकी अपराध के लिए जांच शुरू की थी। बेल्जियम की इस जांच से अमे. रिका के रक्षा मंत्री डोनाल्ड रम्सफील्ड ने यह मान लिया कि सार्वभौमिक न्यायिक क्षेत्र ने अमेरिकी हितों पर सीधा खतरा पहुंचाया है। उन्होंने बुश प्रशासन के अन्य अधिकारियों को एक पत्र लिखा, "अब बस कुछ समय की ही बात है कि अमेरिकी अधिकारियों को जानबूझ कर मुकदमों में फंसाया जाएगा। उन्होंने बेल्जियम को चेतावनी दी कि यदि इस कानून में बदलाव नहीं किया जाता नाटो अपना मुख्यालय ब्रसेल्स से हटा लेगा। जल्दी ही बेल्जियम कानून में बदलाव करने में सक्षम हो गया। अब इसी तरह से सार्वभौमिक न्यायिक क्षेत्र पर समझौता करने के रास्ते पर बढ़ रहा स्पेन अपनी प्रतिष्ठा खो सकता है। सीमा पार हुए उत्पीड़नों के मामले में मुकदमा चलाने के मामले में स्पेन के जज अगुआ रहे हैं और मैड्रिड द्वारा कदम पीछे खींचने का असर दूसरे देशों पर भी दिखेगा। सार्वभौमिक न्यायिक क्षेत्र के आधार पर मुकदमा वास्तव में पहले से ही असामान्य मामलों में होता रहा है (इस पर विवाद हो सकता है कि कोई मामला कितना अनोखा है) । एक अध्ययन में बताया गया है कि द्वितीय विश्वयुद्ध से अब तक सार्वभौमिक न्यायिक क्षेत्र के सही मामले कुछ दर्जन ही सामने आए हैं।

सार्वभौमिक न्यायिक क्षेत्र के मुक. दमों के अभाव से यह पता चलता है कि ज्यादातर राष्ट्रीय कानूनी प्रणालियों में इतना संसाधन या ऐसी सोच नहीं है कि उनके क्षेत्र या नागरिकों से न जुड़े मामलों में भी अभियोग चलाया जाए। वर्ष 2012 से शुरू हुए अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) का मतलब यह है कि अब ऐसे गंभीर अपराधों के मामले में मुकदमा चलाने के लिए एक स्थायी कोर्ट तैयार है जिनमें सार्वभौमिक न्यायिक क्षेत्र की पहुंच होती है। सांसद और जज यह तय कर सकते हैं कि विदेशी जमीन पर हुए किस तरह के अपराधों को हेग स्थित आईसीसी को सौंपा जा सकता है।

लेकिन जो लोग सार्वभौमिक न्याय के पक्षधर हैं उन्हें यह जवाब संतुष्ट नहीं करता। सैद्धांतिक रूप से आईसीसी तिब्बत में चीनी ज्यादती (या आतंकवाद से लड़ाई में अमेरिकी ज्यादती) की जाचं कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इजाजत लेनी होगी, जहां उक्त दोनों महाशक्तियों के पास वीटो पावर है। एक कमजोर से मजबूत न्याय प्रणाली तक पहुंचने में दुनिया ने लंबा रास्ता तय किया है और स्पेन में बदलाव से निश्चित रूप से यह दूरी और बढ़ेगी।

परमपावन दलाई लामा के साथ संवाद

(20 फरवरी, 2014, टाइम मैगजीन)
एलिजाबेथ डायस

टाइम मैगजीन की रिपोर्टर एलिजाबेथ डायस वाशिंगटन डीसी में 19 फरवरी, 2014 को परमपावन दलाई लामा का इंटरव्यू लेते हुए। फोटोः जेमी रसेल/ओएचएचडीएल

अमेरिका के पश्चिमी किनारे के दो हफ्ते लंबे दौरे से पहले तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने बुधवार को टाइम की धर्म संपादक एलिजाबेथ डायस को वाशिंगटन डीसी में 40 मिनट लंबा इंटरव्यू दिया। उन्होंने अमेरिकी विदेश नीति के सामने मौजूद नैतिक चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के खतरे, अपनी जन्म भूमि चीन तथा भारत जहां वह आधी सदी से भी ज्यादा समय से निर्वासन में रह रहे हैं, के बीच स्वस्थ संबंध के महत्व पर प्रकाश डाला। हालांकि, 78 वर्षीय दलाई लामा की अक्सर चीन के अधिकारी आलोचना करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने चीन के नए राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बारे में गर्मजोशी वाले शब्दों का प्रयोग किया। यहां उनसे बातचीत के अंश प्रस्तुत हैः

तिब्बतियों की आज़ादी कभी अमेरिका के लिए बड़ा मसला रहा है, लेकिन आज इस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ है?

कोई भी समस्या जब आती है तो पहले वह नई बात होती है। इसके बाद समय गुजर जाता है...मैं समझता हूं कि तुलनात्मक रूप से तिब्बत मसला हर जगह मजबूत बना हुआ है।

क्या अमेरिका अब चीन में इसलिए

मानवाधिकार मसले उठाने से पीछे हुआ है क्योंकि चीन अब ज्यादा महत्वपूर्ण ताकत बन गया है?

मैं ऐसा नहीं मानता...आजादी, लोकतंत्र, न्याय अमेरिकी सिद्धांत हैं। कुछ लोगों के लिए अर्थव्यवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है...यह गलत है। अफ्रीका, सीरिया की ओर देखें। नैतिक सिद्धांत की कमी की वजह से वहां मानव जीवन का कोई मोल नहीं है। नैतिक सिद्धांत, सच्चाई एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि हम इसे खो देते हैं तो कोई भविष्य नहीं होगा।

आपके हिसाब से किन वैश्विक मसलों पर अमेरिका को ज्यादा ध्यान देना चाहिए?

पारिस्थितिकी। अमेरिका के पूर्वी तट पर इन दिनों असामान्य बर्फबारी देखी जाती है। इसी तरह, भारत और अमेरिका में भी जलवायु पैटर्न में काफी बदलाव आ रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तरी ध्रुव के अभूतपूर्व रूप से पिघलने की वजह से जलवायु में यह बदलाव आ रहा है और इसके असर से ही मौसम में इतना अनिश्चित पैटर्न देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की बात पर गौर करना चाहिए।

फेसबुक और ट्विटर से हमारी खुशहाली में मदद मिलती है या उसे नुकसान होता है?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से कुछ मजबूत है, उसके अंदर कुछ आत्मविश्वास है, तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का दिमाग कमजोर है तो वह और भ्रमित हो सकता है। आप इसके लिए टेक्नोलॉजी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। यह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर करता है।

आपने चरस के चिकित्सीय इस्तेमाल का समर्थन किया है। क्या आपने कभी इसका कश लिया है?

नहीं, कभी नहीं। इस तरह के पदा. र्थों को आमतौर पर विष माना जाता है, ये बहुत बुरे होते हैं। लेकिन कुछ बीमारियों में इसका जानूबझ कर इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए यह डॉक्टरों या वैज्ञानिकों पर निर्भर है। सच्चाई को समझ सकने की योग्यता बहुत अनूठी होती है। हमारा दिमाग बहुत खास तरह का है। इसलिए यदि इसको नुकसान होता है तो यह बहुत खराब बात है। इसलिए अल्कोहल और ड्रग्स बहुत बुरे होते हैं।

आपके हिसाब से औरतों के बारे में बौद्ध दृष्टिकोण से पोप फ्रांसिस और कैथोलिक चर्च क्या सीख सकते हैं?

सामान्य तौर पर कहें तो हर धर्म को अपनी परंपरा का पालन करना होता है, लेकिन कभी–कभी हमें नई सच्चाई के मुताबिक निर्णय लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए महिलाओं के अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं समझता हूं कि परमपावन पोप बहुत यथार्थवादी हैं और काफी सख्त हैं। मैं उनकी इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि उन्होंने एक जर्मन बिशप को बर्खास्त कर दिया जो बहुत शानो–शौकत का खर्चीला जीवन जी रहे थे।

आप उन तिब्बती विरोध प्रदर्शनकारियों के बारे में क्या कहेंगे जो आत्मदाह कर अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं?

सबसे पहली बात तो यह है कि यह बहुत ही दुःखद है। जीवन बहुत कीमती है। लेकिन यह एक बहुत ही संवेदनशील राजनीतिक मसला है। मैं जो कुछ भी कहता हूं चीन के कट्टरपंथी हमेशा ही उसे तोड़–मरोड़ कर पेश करते हैं। इसके अलावा मैं कुछ साल पहले रा. जनीतिक जिम्मेदारी से रिटायर भी हो चुका हूं। इसलिए मेरे लिए अच्छा यही है कि मैं चुप रहूं।

क्या आप मानते हैं कि भारत–चीन की प्रतिद्वंद्विता एशिया के लिए अच्छी बात है और यह तिब्बतियों के हित में अच्छा होगा?

बिल्कुल नहीं। वाजिब अच्छे संबंध अगर परस्पर भरोसे पर आधारित हों तो इससे आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है और साथ ही साथ शिक्षा तथा आध्यात्मिकता को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए भारत और चीन के बीच वास्तविक भरोसा बहाल करने की जरूरत है।

चीन के नए राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बारे में आपके क्या विचार हैं?

वह साहसपूर्ण तरीके से भ्रष्टाचार से निपट रहे हैं, काफी प्रभावशाली और निडर तरीके से। असल विकास ग्रामीण इलाकों में होना चाहिए। नए, बड़े शहर बनाने से कोई हल निकलने वाला नहीं है। चीन के 1.3 अरब लोगों को सच्चाई जानने का पूरा अधिकार है। सेंसरशिप एक अव्यावहारिक तरीका है और इससे वास्तव में असंतोष और संदेह ही पैदा होता है। चीनी न्यायिक प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप बनाना होगा। इसके बाद ही एक अरब गरीब लोगों को कुछ बचाव हासिल हो सकता है।

(एलिजाबेथ टाइम मैगजीन के वाशिंगटन ब्यूरो में कार्यरत हैं)

तिब्बती सांसद मानवाधिकार एवं लोकतंत्र के लिए आयोजित जेनेवा सम्मेलन में शामिल हुई

(धर्मशाला, तिब्बत डॉट नेट, 28 फरवरी, 2014)

निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्य तेनजिन धारडो शार्लिंग मानवाधिकारों एवं लोकतंत्र के लिए छठे जेनेवा वार्षिक सम्मेलन के दौरान तिब्बत पर बोलते हुए।

निर्वासित तिब्बती संसद की सदस्य धारदोन शारलिंग जेनेवा में 25 फरवरी को आयोजित मानवाधिकार एवं लोकतंत्र के 6ठे जेनेवा सम्मेलन में शामिल हुई। यह सम्मेलन मार्च में होने वाले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सालाना सत्र के कुछ दिनों पहले ही आयोजित किया गया। इससे मानवाधिकारों की स्थिति पर तत्क. ाल दुनिया को गौर करने की बात को बल मिला। इस सम्मेलन में सैकड़ों साहसी विद्रोही एवं पीड़ित, आंदोलनकारी और छात्र नेता शामिल हुए। क्यूबा, ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, मिस, तिब्बत और अन्य कई देशों के मानवाधिकार नायक तथा पूर्व राजनीतिक कैदियों ने मानवाधिकार, लोकतंत्र और आज़ादी के बारे में अपने व्यक्तिगत संघर्षों की जानकारी दी। यह सम्मेलन 20 देशों के मानवाधिकार संगठनों के गठबंधन यूएन वाच द्वारा प्रायोजित किया गया था। इन एनजीओ में स्विट्जरलैंड का तिब्बती महिला संगठन भी शा. मिल था।

तिब्बत डॉट नेट को दिए एक इंटरव्यू में धारदोन शारलिंग ने बताया कि उन्होंने सम्मेलन के दौरान यह मसले उठाए हैं कि चीनी शासन के दौरान तिब्बत और तिब्बतियों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पेश है इस इंटरव्यू का अंश:

मार्च में होने वाले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सालाना सत्र को देखते हुए जेनेवा का यह सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है। आपने सम्मेलन के दौरान तिब्बत के भीतर तिब्बतियों द्वारा सामना किये जाने वाले किन चुनौतियों का उल्लेख किया है?

सम्मेलन के प्रमुख वक्ताओं. में से एक होने के नाते मैंने 'महिला अधिकार, मानव गरिमा और समानता' विषय पर अपने विचार रखे। मैंने चीन सरकार की नीतियों

पर जोर दिया जिसमें तिब्बती इलाकों में बड़े पैमाने पर चीनी प्रवासियों को बसाए जाने की बात भी शामिल है जिसकी वजह से तिब्बती पहचान और सांस्कृतिक विरासत पर खतरा पैदा हो रहा है। तिब्बत में खराब होती मानवाधिकार की स्थिति पर मैंने चिंता जताई जिसके तहत तिब्बत में मर्दों, औरतों दोनों के चीन सरकार द्वारा भारी दमन को रेखांकित किया। इसके अलावा, तिब्बत में महिलाओं की स्थिति से पता चलता है कि चीन महिला मानवाधिकारों जैसे प्रजनन के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, भेदभाव, जबरदस्ती और हिंसा से मुक्त रहने का अधिकार आदि के बारे में अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्य मानकों और संयुक्त राष्ट्र समझौतों के लिए प्रतिबद्ध नहीं है।

मैंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सुझाव दिया कि वे तिब्बत के मसले पर चीन के साथ संपर्क मजबूत करें और यह सुनिश्चित करें कि चीन सरकार तिब्बतियों के वैधानिक शिकायतों का समाधान करे। सबसे पहले, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य बनने के अपने वायदे को पूरा करे। दूसरे, आने वाले यूएनएचआरसी के 25वें सत्र में फॉलो–अप का कोई तरीका अपनाएं कि चीन पर पिछली सार्वभौमिक समीक्षा के बाद तिब्बत के बारे में दिए सुझावों पर कितना अमल हुआ है। चीन पर इस बात का दबाव बनाने के लिए भी अनुरोध किया गया है कि वह संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त नवी पिल्लई के सितंबर में दूसरा कार्यकाल पूरा हो जाने से पहले उनके तिब्बत दौरे की इजाजत दे।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय की बार–बार अपील के बावजूद तिब्बत के भीतर दमन खत्म नहीं हो रहा है। क्या जेनेवा सम्मेलन में इसके लिए किसी तरह के कार्य योजना की बात की गई है कि तिब्बत में चीन द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन को किस तरह से खत्म किया जाए?

यह सम्मेलन एक सालाना सिविल सोसाइटी का मंच है जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे पर तात्कालिक परिस्थितियों को रखने कोशिश की जाती है। इसमें दुनिया भर के सैकड़ों बागी, आंदोलनकारी, राजनयिक और पत्रकार जुटते हैं। हालांकि, तिब्बत के लिए अलग से कोई कार्य योजना तो नहीं पेश की गई है, लेकिन सम्मेलन में यह वचन दिया गया कि चीन जैसे 'तानाशाह' देशों को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल करने के लिए दबाव बढ़ाया जाएगा। यह प्रोत्साहित करने वाली बात थी कि सत्र के करीब एक–तिहाई वक्ताओं ने तिब्बत के भीतर की गंभीर हालात का उल्लेख किया और कहा कि ऐसा सुनिश्चित करना होगा कि चीन, तिब्बत में अपने कार्यों में जवाबदेह रहे।

क्या इस सम्मेलन में मुख्य भूमि चीन से भी कोई आया था। तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में उनका क्या विचार था, खासकर यह देखते हुए कि तिब्बत में आत्मदाह रूपी विरोध प्रदर्शन की दुःखद घटनाएं हो रही हैं?

दुर्भाग्य से सीरिया, क्यूबा, वियतनाम के प्रतिनिधियों के विपरीत मुख्य भूमि चीन से कोई वक्ता नहीं आया था, सिवाय चीन मे लोकतंत्र के लिए आंदोलन करने वाले डॉ. यांग जियानली और चीन से भाग चुके विद्रोही छेन गुआंगछेंग के, लेकिन दोनों अब अमेरिका में रहते हैं।

हम यह मान सकते हैं कि बहुत लोगों ने इसमें भागीदारी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया होगा लेकिन चीनी राजनयिकों की उन पर कड़ी नजर रही होगी। कुल मिलाकर इस सम्मेलन में तिब्बत के भीतर आत्मदाह के मामलों पर चिंता जताई गई और इस पर चीनी प्रतिक्रिया पर भी जो कि आत्मदाह का अपराधीकरण कर रहा है, आत्मदाह करने वालों के परिजनों को मौत की या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा रही है। महत्वपूर्ण यह है कि यह सम्मेलन महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 25वें सत्र के एक हफ्ते पहले हुआ जहां चीन सार्वभौमिक नियतकालिक समीक्षा सुझावों पर प्रतिक्रिया देगा।

सम्मेलन का मुख्य आकर्षण रहे नेत्रहीन चीनी आंदोलनकारी छेन गुआंगछेंग जिन्हें वर्ष 2014 का जेनेवा सम्मेलन साहस अवॉर्ड दिया गया।

चीन के खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड के बावजूद उसे पिछले साल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना दिया गया। इसकी सम्मेलन के दौरान क्या प्रतिक्रिया रही?

सम्मेलन के दिन इसके आयोजनक यूएन वाच, जो कि दुनिया भर के 20 मानवाधिकार एनजीओ का गठबंधन है, ने "तानाशाह मुक्त मानवाधिकार परिषद" का अभियान शुरू किया। भागीदारों और वक्ताओं ने संकल्प लिया कि वह एचआरसी से चीन, सऊदी अरब, रूस और क्यूबा को बाहर करके रहेंगे।

ओबामा–दलाई लामा मुलाकात से पता चलता है कि अमेरिका कितना ईर्ष्यालु है: चीनी एक्सपर्ट

(डेविड वरटाइम, फॉरेन पॉलिसी , 21 फरवरी, 2014)

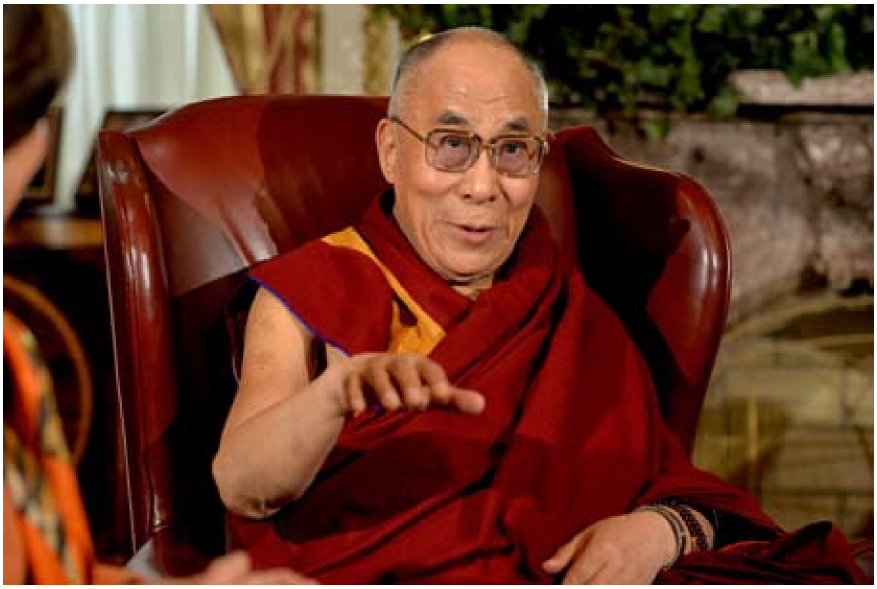

वाशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल के 6 मार्च के दौरे के दौरान अपने विचार रखते हुए परमपावन दलाई लामा। फोटोः सोनम जोकसांग

गत 21 फरवरी को पत्रकारों के लिए प्रवेश निषेध वाले एक बंद कमरे की मुलाकात में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने निर्वा. सित तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा की मेजबानी की। वही दलाई लामा जिन्हें चीन "भेड़ के कपड़ों में भेड़िया" बताता है।

अनुमान के मुताबिक ही चीनी अधि िकारियों ने इस मुलाकात के पहले ही इसका काफी विरोध किया और चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने 21 फरवरी को चेतावनी दी कि इससे चीन–अमेरिका संबंधों को गंभीर क्षति पहुंचेगी। जब भी अमेरिका या अन्य कोई दलाई लामा की तारीफ करता है तो चीन के ऐसे बयान और नाराजगी सामने आती है क्योंकि वह दलाई लामा को तिब्बती आज़ादी के लिए प्रयास करने वाली ताकत मानता है। दूसरी तरफ, चीन के भीतर स्थानीय मीडिया ने भी इस पर काफी नाराजगी जाहिर की है और कई बड़े पोर्टल पर आई खबरों में विदेश मंत्रालय ने यह दावा किया कि यह वार्ता चीन के आंतरिक मामलों में बेवजह दखल है। व्हाइट हाउस मैप रूप में ओबामा और दलाई लामा की मुलाक. ात के कई घंटों पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली में प्रतिष्ठित रेनमिन यूनिवर्सिटी, बीजिंग में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर और वाइस डीन जिन कानरोंग का एक इंटरव्यू छपा जिसमें उन्होंने अमेरिका–चीन रिश्तों पर खास तौर से बात की। उन्होंने अखबार से कहा कि इस वार्ता के पीछे वह तीन तरह की प्रेरणा देखते हैं: चीन का राजनयिक प्रदर्शन जबर्दस्त है जिसकी वजह से अमेरिका पर "काफी दबाव" बन गया है। इंटरव्यू की शक्ल वाले इस आलेख में कहा गया कि वर्ष 2013 में ही पड़ोसी देशों के साथ राजनय के मामले में एक नई यथास्थिति की पहल कर चीन ने अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ा ली थी जिससे उसे कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जिन ने कहा कि चीन ने इस दौरान अमेरिका की राजनयिक उपलब्धियों को बौना कर दिया है। जिन ने कहा कि दलाई लामा से मुलाकात कर एक तरह से अमेरिका "चीन को हाथ खींचकर पीछे रखना चाहता है।"

जिन ने चीनी अधिकारियों के बीच आम देखी जाने वाली उस साझा आवेग का कोई विरोध नहीं किया जिसके तहत तिब्बती आध्यात्मिक नेता के खिलाफ अंधाधुंध हमला बोला जा रहा है। जिम का कहना है कि ओबामा की यह मुलाकात दलाई गुट को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का ही हिस्सा है जो "नैतिक बल काफी कमजोर हुआ है, मार्च 2011 में दलाई लामा के निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रमुख पद से हटने के बाद।"(हार्वर्ड में पढ़े लोबसांग सांगे अप्रैल 2011 में हुए चुनावों में जीतकर दलाई लामा की जगह 30 देशों में रहने वाले निर्वासित तिब्बतियों की सरकार के प्रमुख बने हैं। चीन की सरकारी मीडिया इसे दलाई गुट कहकर यह दिखाना चाहती है कि दलाई लामा का प्रभाव बहुत छोटे से हुल्लड़बाज अल्पसंख्यक तिब्बतियों तक ही है और इस गुट को तिब्बत की "आज़ादी का आंदोलन" चलाते रहने के लिए ओबामा के मदद की जरूरत है। इस आलेख में जिन ने कहा है कि ओबामा मध्यावधि चुनावों से पहले "मानवाधिकार कार्ड" खेल रहे हैं। जिन ने कहा कि अमेरिका–चीन संबंध "दोहरी प्रकृति" का है जिसमें अमे. रिका "कभी–कभी आपसे सहयोग करने की दृढ़ता दिखाता है, लेकिन आपकी राह में अडंगा भी लगाता रहता है।" उन्होंने कहा कि चीन एक उभरती हुई ताकत है, इसलिए इस तरह की बात स्वाभाविक है।

ड्रैगन इन द लैंड ऑफ सनो

तिब्बती इतिहासकार सेरिंग शाक्य

तिब्बत को हमेशा के लिए निगल लिया गया है

सेठ फइसोन न्यूयॉर्क टाइम्स

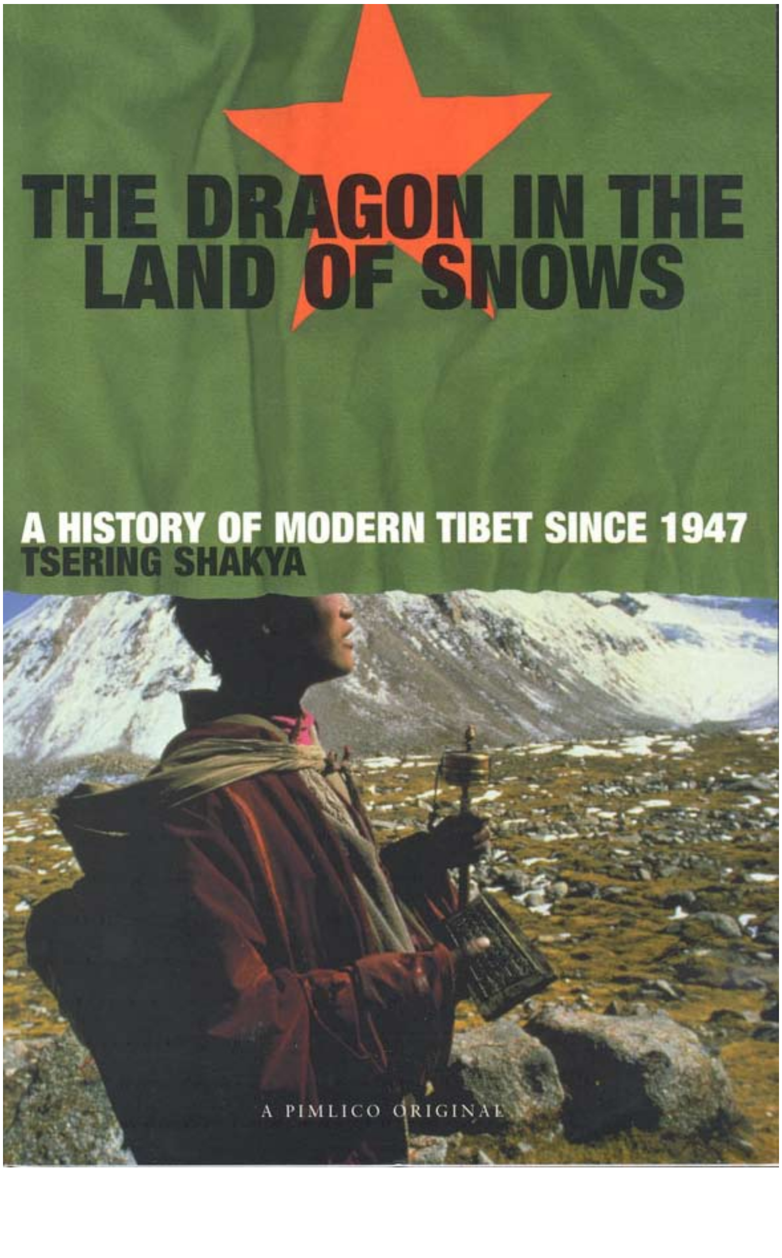

आधुनिक तिब्बत की कहानी ह्रदय विदारक है। इसमें इस रहस्यमय हिमालयी भूमि के आकर्षक भले ही मध्य युगीन हो, अलगाव से उसके अड़ियल पड़ोसी चीन द्वारा आधुनिक प्रभुत्व का एक हिंसक वाकया है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें दलाई लामा, माओ, नेहरू और तिब्बत की दूसरी धार्मिक हस्ती पंचेन लामा जैसे विशद चरित्र हैं। चीन के गहन दमन अभियान से लेकर उम्मीद और आंशिक खुलेपन के क्षणों के बीच तिब्बत लगातार तिब्बतियों और चीनियों के नितांत धार्मिक और राजनीतिक मतभदों का शिकार है।

वैश्विक मंच पर राजनयिक कूटनीति ने भारत, ब्रिटेन और अमेरिका को 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जे से पहले एक लगातार बदलते प्रतिद्वंद्विता के जाल में फंसाते हुए तिब्बत पर अत्यंत अव्यवस्थित प्रभाव का रास्ता बनाया। दूसरी तरफ, जमीनी स्तर पर तिब्बती बौद्धों के धार्मिक उमंग का टकराव कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से होने लगा। अपरिहार्य रूप से बुरे इरादों की वजह से लाखों साधारण तिब्बती जो गरीब और काफी धर्मपरायण लोग थे, जिनका जीवन याक चराने, मामूली खेती और मंदिरों में पूजा तक सीमित था, उनका सामना जबरन कम्युनिस्ट सिद्धांत और नस्लीय भेदभाव की सच्चाई से हुआ जिसका विनाशक परिणाम हुआ। आधुनिक तिब्बत एक ऐसी कहानी है जिसे बताना मुश्किल है, तिब्बत और चीन की राजनीति एवं संस्कृति इतनी जटिल है और इतने जुनूनी तरह से पक्षपातपूर्ण है जो इतिहासकारों ने पहले कभी नहीं देखा है। तिब्बत के ज्यादातर आधुनिक इतिहास में तिब्बती या चीनी पक्ष में झुकाव देखा जा सकता है।

लेकिन अब एक ब्रिटिश तिब्बती इतिहासकार सेरिंग शाक्य ने तिब्बत के बारे में एक गहरी आंतरिक दृष्टि वाली और संपूर्ण लेखा–जोखा पेश किया है जो कि हर बड़े खिलाड़ी के चारित्रिक दोष को उजागर कर देता है। तिब्बती, चीनी, ब्रिटिश और अमे. रिकी स्रोतों के हवाले से शाक्य ने एक प्रमाणिक और आसानी से पढ़ने योग्य कथा पेश की है। "ड्रैगन इन द लैंड ऑफ स्नोज" एक पीढ़ी या उससे भी ज्यादा के आधुनिक तिब्बत का निर्णायक इतिहास साबित हो सकता है।

चीनी शासन की सिर्फ आलोचना करने की जगह शाक्य ने इस बारे में काफी विशेषज्ञता से बताया है कि चीनी नीतियों में बदलाव की क्या वजह रही है, किस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर के छल–कपट ने तिब्बतियों के जीवन को प्रभावित किया और लाशों तथा नष्ट मंदिरों, मठों का एक भयावह दौर सामने आया। उनका तरीका काफी निष्पक्ष है, किसी गुस्से या निराशावाद से बचते हुए। इसकी वजह से पाठक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि तिब्बत की दुखद कहानी किसी सुनियोजित चीनी योजना का हिस्सा नहीं है जैसा कि तिब्बती शरणार्थी दावा करते हैं या कोई भारतीय–अमेरिकी षडयंत्र नहीं है, जैसा कि चीनी नेताओं का दावा रहता है। इसकी जगह, यह प्रतिस्पर्धी हितों, गलतफहमी, पीठ में छुरा घोंपने और राजनीतिक औचित्य साबित करने का नतीजा है।

शाक्य की कहानी 1947 से शुरू होती है, जब ब्रिटिश भारत छोड़कर चले गए और तिब्बत पर उनका प्रभाव भी खत्म हो गया। उस समय तिब्बत काफी कमजोर पड़ गया था, धर्मगुरुओं के एक छोटे से समूह द्वारा शासित था, कुलीनतंत्र और एक दलाई लामा के सहारे जिनकी उम्र महज 12 साल थी और वह एक धार्मिक एवं राजनीतिक नेता की अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। देश के दुर्गम पहाड़ों और सड़कविहीन सीमाओं ने विदेशी आक्रांताओं को इस पर हमले के लिए हमेशा ही हतोत्सा. हित किया जिसकी वजह से तिब्बत की सेना कुछ पुराने हथियारों से लैस एक निम्नस्तरीय सेना थी। इसी प्रकार इसका राजनीतिक ढांचा भी इतना अपरिपक्व था कि जब 1950 में चीनी सेना पहुंच गई तो किसी तरह का प्रतिरोध का समन्वय नहीं कर पाई।

भारत की ओर मदद के लिए देखना भी निरर्थक साबित हुआ क्योंकि तब नए–नए प्रधानमंत्री बने नेहरू चीन के साथ दोस्ताना संबंध चाहते थे जो कि उनके हिसाब से उपनिवेशवाद के दौर से बाहर हो चुकी दुनिया के लिए जरूरी था। यह एक गलत अनुमान साबित हुआ और भारत ने 1962 के चीनी युद्ध में इसकी भारी कीमत चुकाई, जिसकी वजह से दोनों देश प्रतिद्वंद्विता के ऐसे दौर में पहुंच गए जिसका दशकों तक तिब्बत को कड़वा नतीजा भुगतना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक रूप से तिब्बत मसले से दूर रही रहने का निर्णय लिया, लेकिन एलेन डलेस की सीआईए ने तिब्बती गुरिल्लाओं के लिए गुप्त तरीके से समर्थन की व्यवस्था की। एक समय इन गुरिल्लाओं को प्रशांत महासागर के द्वीप साइपन और कोलोरेडो प्रशिक्षण के लिए ले जाया गया। हालांकि, शाक्य यह कहते हैं कि सीआईए ने दलाई लामा के तिब्बत से 1959 में निर्वासित होकर भारत जाने की पूरी योजना बनाई थी और वह यह दिखाते हैं कि किस तरह से सीआईए की मामूली भूमिका से चीन को अपने इस दृष्टिकोण को स्थापित करने में मदद मिली कि तिब्बत को अस्थिर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय षडयंत्र हो रहा है।

लेखक ने जनक्रांति की चीर–फाड़ करने की पूरी कोशिश की है जिसकी वजह से दलाई लामा को निर्वासित होना पड़ा। वह तिब्बत में सांस्कृतिक क्रांति के कोलाहल को दो वाम धड़ों के बीच टकराव का साफ नतीजा बताते हैं, जिसके आधार पर वह घटनाओं को ऐसे प्रभावशाली विवरण के साथ पेश करते हैं जिससे चीनी राजनीति की गहरी समझ पैदा होती है। इसी तरह उन्होंने चीन और दलाई लामा के बीच 1980 के दशक में चली गोपनीय वार्ताओं का भी गहन लेखाजोखा पेश किया है।

आश्चर्यजनक रूप से इस पुस्तक के नायक पंचेन लामा हैं जिन्हें अक्सर चीनी शासन को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर लेने की वजह से देशद्रोही के रूप में पेश किया जाता रहा है। दलाई लामा के बाद तिब्बती धार्मिक पदानुक्रम में दूसरे स्थान पर रहने वाले पंचेन लामा को असल में चीनी राष्ट्रवादियों ने ही आगे बढ़ाया था ताकि उन्हें अपने तिब्बती कठपुतली के रूप में इस्तेमाल कर सकें, एक ऐसी भूमिका जिसे कम्युनिस्टों ने हमेशा बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन पंचेन लामा पर्दे के पीछे तिब्बतियों के लिए ज्यादा कानूनी और धार्मिक अधिकार हासिल करने की कोशिश करते रहे। सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने निडरता से माओ से संपर्क किया और उन चीनी अधिकारियों की तीखी आलोचना की जिन्होंने तिब्बत में लोगों के जीवन को दयनीय बना दिया था, अपने कर्मचारियों के तमाम अनुरोध के बावजूद कि इस तरह का कदम राजनीतिक रूप से आत्मघाती साबित हो सकता है। वास्तव में अपनी तीखी जबान की वजह से ही पंचेन लामा को दस साल जेल में बिताने पड़े और जब वह 1978 में बाहर आए तो उन्होंने तत्काल नए सिर से ऐसे प्रयास करने शुरू कर दिए। शाक्य इस बात पर संक्षिप्त रोशनी डालते हैं कि 1989 में महज 50 वर्ष की कम उम्र में पंचेन की मौत कैसे हो गई, जिससे चीन के षडयंत्र की चर्चा होने लगी। उन्होंने यह बताया है कि चीन को वास्तव में तिब्बतियों को संतुष्ट करने के लिए पंचेन लामा की सख्त जरूरत थी और पिछले साल जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुए तो उनको काफी याद किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के बाद चीनी शासन ने सैनिक शासन घोषित कर दिया और दमन का एक और दौर शुरू हुआ।

पुस्तक के अंत में लेखक ने पंचेन लामा के नए अवतार को लेकर हुए बवाल का तीखा विश्लेषण किया है, दस साल का एक उम्मीदवार नजरबंद है और दूसरा एक चीनी हस्ती के रूप में कठिन जीवन जी रहा है। इसमें आज के तिब्बत और चीन की समस्याओं को ठोस तरीके से पेश किया गया हैः किस तरह से राजनीतिक वैधता इस पहाड़ी मरुस्थलीय पठार में दलाई लामा, एक अतुलनीय नैतिक चेहरा जो भौतिक रूप से अनुपस्थित है और चीन में बंटा हुआ है जो बलपूर्वक वहां मौजूद तो है, लेकिन नैतिक रूप से अशक्त है। यह एक ऐसा दुःखद हालात है जिसके इस इलाके में लंबे समय तक बने रहने की आशंका दिख रही है।